



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 12 दिसम्बर, 2000/21 अग्रहायण, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 नवम्बर, 2000

संख्या एल० एल० आर०-बी० (14) 13/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अभियोजन विभाग, हिमाचल प्रदेश में, संयुक्त निदेशक (अभियोजन) वर्ग-I (राजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना में संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग संयुक्त निदेशक (अभियोजन) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियाँ.—(1) इस विभाग की अधिसूचना सं० एलएलआर-बी (14) 13/84. तारीख 5 जुलाई, 1989 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग संयुक्त निदेशक (अभियोजन) के पद में भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1989 का एतद्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है जहाँ तक कि ये संयुक्त निदेशक (अभियोजन) के पद को लागू हों।

(11) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (I) के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

देव स्वरूप,

विस्तृत्युक्त एवं सचिव।

उपाबन्ध "क"

अभियोजन विभाग, हिमाचल प्रदेश में संयुक्त निदेशक (अभियोजन) वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम	संयुक्त निदेशक (अभियोजन)
2. पदों की संख्या	1 (एक)
3. वर्गीकरण	वर्ग-I (राजपत्रित)
4. वेतनमान	रूपये 13500-400-15900-450-16800.
5. चयन पद अथवा अचयन पद	चयन
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	45 वर्ष व इससे कम :

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में रत व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि यदि तदर्थ आधार पर या संविदा आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिकव्य हो गया हो तो, वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में किसी शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतना ही शिथिलीकरण किया जा सकेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त

निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन के पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्तर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप में आमेलित किये गये हैं/किये गये थे ।

टिप्पण.—(1) सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिन से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को यथास्थिति आवेदन आमन्त्रित करने के लिये विज्ञापित किया जाता है या नियोजनालयों को अधिगृहित किया जाता है ।

(2) अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं ।

अनिवार्य अर्हताएं :

- (i) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से विधि स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य
- (ii) उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय में व्यवसायिक अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष से कार्य कर रहा हो ।

बांछनीय अर्हताएं

हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रेषण की दशा में लागू होंगी या नहीं ?

आयु : लागू नहीं
शैक्षणिक अर्हताएं : लागू नहीं

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकता है जैसा कि

सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों को अभिलिखित करके आदेश दिया जाए।

10 भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

11 प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा।

उपरोक्त स्वम्भ 7 में विहित शैक्षणिक अर्हताएं पारपूर्ण करने वाले उप-निदेशक (अभियोजन) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में (31-3-1998 तक) की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-1998 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी। परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1998 तक तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुमरण में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है वहाँ अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, को कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तु की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने के विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जायेगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोरसिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टेक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व 31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु 31-3-98 तक की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना ?

जैसी कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।

जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो

14. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षा

किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी निम्न-लिखित अवश्य होना चाहिए:—

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा या

(घ) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थाई निवास के आशय से आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देश, कोनिया, युगांडा, युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पहले तांजानिका और जमीवारा), जांबिया, मालवा, जेयरे और

Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Joint Director (Prosecution) Class-I (Gazetted) in the Department of Prosecution, Himachal Pradesh as per Annexure 'A' attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Prosecution Department, Joint Director (Prosecution) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2000.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and savings.*—(1) The Himachal Pradesh Prosecution Department (Recruitment and Promotion Rules, 1989, notified *vide* this Department Notification No. LLR-B-(14)13/84 dated 5th July, 1989 are hereby repealed to the extent these are applicable to the post of Joint Director (Prosecution).

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed *vide* rule (1) *supra*, shall be deemed to have validly made, done or taken under these rules.

By order,

DEV SWARUP,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JOINT DIRECTOR
(PROSECUTION (GAZETTED) CLASS-I, IN THE DEPARTMENT OF PROSECUTION,
HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post	Joint Director (Prosecution)
2. Number of posts	1 (One)
3. Classification	Class-I (Gazetted)
4. Scale of pay	Rs. 13500-400-15900-450-16800.
5. Whether selection post or non-selection post ?	Selection
6. Age for direct recruitment	45 years and below :

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any

relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial Constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note—1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

2. Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.

(a) *Essential Qualifications :*

(i) Bachelor's Degree in Law or its equivalent from a recognised University/Institution duly recognised by the Central/ State Government.

(ii) Must possess atleast seven years experience as a practising Advocate in High Court/District Court.

(b) *Desirable qualifications :*

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees ?
Age : Not applicable
Educational Qualifications : Yes as prescribed under column No. 11 below.
9. Period of probation, if any
Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.
100 % by promotion failing which by direct recruitment.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.
By promotion from amongst the Deputy Director (Prosecution) subject to fulfilling the Educational Qualifications prescribed in Column No. 7 above with 3 years regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-1998) service, if any, in the grade.

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-98, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules, provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-98) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules:

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service rendered upto 31-3-1998 as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C is to be consulted in making recruitment.
14. Essential requirement for a direct recruitment.

As may be constituted by the Government from time to time.

As required under the law.

A candidate for appointment to any service or post must be,—

- (a) a citizen of India, or
- (b) a subject of Nepal, or
- (c) a subject of Bhutan, or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st

January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malwa, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of Himachal Pradesh.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of Himachal Pradesh.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.

Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva voce* test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.

16. Reservation

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination

Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination rules, 1997.

18. Powers to relax

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the H.P.S.C., relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.